

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – चावण्डदान चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: टी.ए. 80/2015

पंजीयन दिनांक: 10.12.2015

रोशनलाल पिता केसरिमल जाति महाजन बोहरा निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला  
चित्तौड़गढ़

—अपीलान्ट

बनाम

जाकिर पिता अहमद जाति मुसलमान निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्ट



अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं  
आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी  
प्रकरण 09/2013 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.07.2015

उपस्थित वक्त बहस: 1. कृष्णगोपाल व्यास – अधिवक्ता अपीलान्ट  
2. भेरूलाल वैष्णव – रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 13.04.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय  
मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलान्ट  
विपक्षी के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा पहुँना पटवार हल्का पहुँना तहसील  
राशमी के बरून हल्का आबादी मे रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 1794/2  
रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व आराजी नम्बर 1788/2 रकबा 8 बिस्वा स्थित है। अपीलान्ट विपक्षी  
के खातेदारी की आराजी नम्बर 1775 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि  
पर जाने आने हेतु सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 149 डामरीकृत सडक से होता हुआ  
अपीलान्ट विपक्षी की आराजी नम्बर 1775 की पूर्वी मेड पर होता हुआ आराजी नम्बर 1786  
किस्म रास्ते पर प्रवेश कर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी अपनी आराजीयात मे आता जाता है। तथा  
रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अनुतोष चाहा कि विपक्षी अपीलान्ट की आराजी नम्बर 1775  
रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के पूर्वी मेड पर मौजूद है। मार्ग 15 फीट चौड़े व 330 फीट लम्बे  
मार्ग को कायम रखते हुए को राजस्व रेकार्ड मे अंकित कराया जावे। अधीनस्थ विचारण  
न्यायालय मे उक्त प्रकरण मे दिनांक 02.03.2015 की आदेशिका मे प्रकरण की सुनवाई

1-0  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आगामी पेशी 15.06.2015 नियत की गई। व बिना सूचना दिये उक्त प्रकरण को दिनांक 04.06.2015 को नियत कर आगामी तारीख पेशी 14.03.2015 को लोक अदालत में नियत की व उसके पश्चात् 15.06.2015 को पत्रावली नियत कर आगामी पेशी दिनांक 11.07.2015 में एक तरफा में बिना कोई सूचना दिये पत्रावली को लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण बिना साक्ष्य सबुत लिये बिना जवाब दावा प्रस्तुत कराये अपीलान्त विपक्षी की अनुपस्थिति में राजीनामे के आधार पर निर्णित कर दी।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 11.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्त विपक्षी ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई व अपील म्याद बाहर होने से अपीलान्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश के विरुद्ध अपीलान्त विपक्षी की ओर से इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्त प्रार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिससे म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। जिसमें वर्णित तथ्य विश्वसनीय होने से अपीलान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्त प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट प्रार्थी की आराजीयात कृषि भूमि नहीं होकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। मात्र राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज होने से रेस्पोंडेन्ट प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए का सहारा लिया गया है। उक्त आराजीयात पर आने-जाने का अन्य वैकल्पिक रास्ता होते हुए रेस्पोंडेन्ट प्रार्थी ने अपीलान्त विपक्षी की आराजी नम्बर 1775 की पूर्वी मेड पर रास्ता मांगा गया है। व अपीलान्त विपक्षी को बिना सुने लोक अदालत में बिना किसी राजीनामे के अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय का निर्णय बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत के तहत पारित किया गया है।

जिससे अपीलान्त विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

20  
राजस्थान अपीलान्त विचारण न्यायालय (राज.)

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट प्रार्थी ने अपनी बहस में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधिपूर्ण व न्यायोचित होना बताया। व यह निवेदन किया है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोजेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रास्ते से सम्बन्धित होकर अन्यायपूर्ण आवश्यक प्रकृति का था जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने संक्षिप्त कार्यवाही करते हुए रास्ता दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है। जो न्यायोचित है। अपीलान्त विपक्षी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है जो निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तों की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोजेन्ट प्रार्थी ने अपनी आराजीयात पर आने-जाने के लिये अपीलान्त विपक्षी के खातेदारी की आराजी नम्बर 1775 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के पूर्वी मेड पर रास्ता चाहने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 15.05.2013 को तहसीलदार राशमी की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें उक्त आराजीयात अपीलान्त विपक्षी के खातेदारी में दर्ज होना अंकित किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जमाबन्दी में भी उक्त आराजी अपीलान्त विपक्षी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। पटवारी हल्का पहुँचा ने अपील रिपोर्ट में अंकन किया कि खातेदार को अपनी भूमि में होकर रास्ते की आवश्यकता अतिरिक्त सुविधा के लिये है जिससे यह प्रतीत होता है कि आने-जाने का रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध है जिसकी विस्तृत जांच की जाना अपेक्षित है। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलान्त विपक्षी को बिना सुने अपीलान्त विपक्षी की आराजी नम्बर 1775 की पूर्वी मेड पर रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश बिना राजीनामे के बिना विपक्षी को सुने बिना लोक अदालत के तहत बिना लिखित राजीनामे पारित किया गया है। जिससे अपीलान्त विपक्षी अधीनस्थ न्यायालय में न्याय से भी वंचित रहा है। यदि अपीलान्त विपक्षी को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिया जाता तो अपीलान्त सभी तथ्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करता व उक्त सभी तथ्यों का अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जाकर न्यायोचित निर्णय पारित किया जा सकता था। विवादित आराजीयात की जमाबन्दी में बैंक रहन का दाखला अंकित है। प्रार्थी रेस्पोजेन्ट ने सम्बन्धित बैंक को पक्षकार कायम नहीं किया है। जिससे भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश न्यायोचित नहीं है जिससे अपीलान्त विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।



10  
राजस्थान अपील प्राधिकरण  
जयपुर (राज.)

फलस्वरूप अपील अपीलान्त विपक्षी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी प्रकरण संख्या 09/2013 प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 11.07.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट ली जाकर उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर नव निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।



(चावण्डदान चारण)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़